राजस्थान झील संरक्षण एंव विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित

पिछौला झील, फतेहसागर झील एवं उदयसागर झील को संरक्षित करने के लिए झील क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में उदयपुर जिला स्तरीय झील विकास प्राधिकरण समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन।

स्वायत्त शासन विभाग के कांफ्रेस हॉल में मंगलवार को प्रातः 10:00 बजे राजस्थान झील संरक्षण एवं विकास प्राधिकारण की बैठक प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई।

बैठक उदयपुर जिला स्तरीय झील विकास प्राधिकरण समिति द्वारा पिछौला झील, फतेहसागर झील एवं उदयसागर झील को संरक्षित करने के लिए झील क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जायेगी।

बैठक में जिला स्तरीय झील संरक्षण एवं विकास समिति अजमेर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावों को अपूर्ण होने की स्थिति में आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

ऊर्जा संरक्षण दिवस – 2016 के अवसर पर प्रदेश को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरूस्कार से सम्मान दिया गया

एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ऊर्जा संरक्षण दिवस–2016 (14 दिसम्बर, 2016) के अवसर पर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के ''राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरूस्कार–2016 (नेशनल एनर्जी कंजरवेशन अवार्ड–2016)'' केन्द्रिय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह ली मेलेडियन होटल, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया।

इसी प्रकार एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरूस्कार – 2016 स्वायत्त शासन विभाग को जयपुर को 14 दिसम्बर, 2016 को इंद्रलोक ऑडिटोरियम, भट्टारक जी की नसीया, टोंक रोड़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अधीक्षण अभियन्ता एवं आयुक्त विद्युत श्री महेन्द्र कुमार बैरवा को प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग श्री संजय मल्होत्रा द्वारा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त समारोह में रतननगर नगरपालिका एवं चुरू नगरपरिषद को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया।

उल्लेखनीय है कि एनर्जी सेविंग परियोजना (एल.ई.डी. लाईट) के तहत देश में नवम्बर, 2016 तक 14 लाख 23 हजार 748 नग लाईटें लगायी गई थी। जिसमें से प्रदेश में सर्वाधिक एल.ई.डी. लाईटें 5 लाख 37 हजार 705 नग लगाई गई है। इस प्रकार से स्ट्रीट लाईट राष्ट्रीय प्रोग्राम ''डैशबोर्ड'' के अनुसार राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक एल.ई.डी. लाईटें लगायी गई है। इसी प्रकार दुसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश तथा तृतीय स्थान पर नई दिल्ली है। डैशबोर्ड पर देश में प्रतिदिन प्रतिराज्य लगने वाली एल.ई.डी. लाईट की संख्या अंकित की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश द्वारा ऊर्जा बचत के क्षेत्र में किये गये विशेष प्रयास को देखते हुए ''राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरूस्कार–2016 (नेशनल एनर्जी कंजरवेशन अवार्ड–2016)'' प्रदान किया गया है।

प्रदेश में एनर्जी सेविंग एल.ई.डी. लाईट परियोजना मार्च 2017 तक प्रदेश में पूर्ण होगी। परम्परागत सोडियम व ट्यूबलाईटों के स्थानों पर एनर्जी सेविंग की एल.ई.डी. लाईट लगाने से लगभग 55 से 60 प्रतिशत ऊर्जा बचत होगी। प्रदेश में अभी तक 35 शहरी निकायों में एल.ई.डी.

लाईट लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिनमें से झालावाड़, माउण्ट आबू, पुष्कर, रतननगर, रतनगढ़, धौलपुर, पाली, उदयपुर, अजमेर, नागौर, आमेट, विद्याविहार, पिलानी, नाथद्वारा, राजसमंद, नवलगढ़, लक्ष्मगढ़, बिसाऊ, डीडवाना, जैसलमेर, सांगोद, कैथून, नीम का थाना, निवाई, जोबनेर, भिवाड़ी, पिड़ावा, निम्बाहेड़ा, किशनगढ़, मकराना, भीलवाड़ा, अकलेरा, चित्तौड़गढ़, रावतभाटा शामिल है। प्रदेश के 48 शहरी निकाय क्षेत्रों में एल.ई.डी. लाईटें लगाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है तथा 7 शहरी निकायो में सर्वे का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 98 शहरी निकाय क्षेत्रों में एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार के सफलतम तीन वर्ष पूर्ण होने पर अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ

राज्य सरकार के सफलतम तीन वर्ष पूर्ण होने पर अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने गुरूवार 15 दिसम्बर, 2016 को 11:30 बजे नगर निगम जयपुर, मुख्यालय, टोंक रोड़, जयपुर में किया।

नगर निगम मुख्यालय, लाल कोठी, टोंक रोड़ पर दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया। उन्होने इस अवसर पर बताया कि राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के 12 शहरों में प्रतिदिन 80 वाहनों के माध्यम से 5 रूपये में नाश्ता एवं 8 रूपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। योजना के द्वितीय चरण में योजना से प्रदेश के अन्य शहरों को भी जोड़ा जायेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों, रिक्शें वालो, ऑटो वाले, ठेले वाले, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं एवं अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है।

उन्होनें बताया कि जयपुर में यह योजना नगर निगम जयपुर कार्यालय के अलावा, गोविन्द देव जी के मन्दिर, चांदी की टकसाल, सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर टोंक रोड़, रेल्वे स्टेशन के बाहर एवं सोड़ाला चौराहे से प्रारम्भ की गई है। एक पखवाड़े में पुरे प्रदेश में 80 अन्नपूर्णा वैन कार्य करने लगेंगी।

योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 12 शहरों में कुल 80 अन्नपूर्णा वैन लगायी जायेगी। जिन पर भोजन उपलब्ध होगा। यह वैन मुख्य रूप से जयपुर में 25, जोधपुर में 5, कोटा में 10, अजमेर में 5, बीकानेर में 5, उदयपुर में 5, भरतपुर में 5, बारां में 3, बांसवाड़ा में 4, डूंगरपुर में 4, प्रतापगढ़ में 3, और झालावाड़–झालरापाटन में 6 अन्नपूर्णा वैन लगायी जायेंगी।

उन्होनें बताया कि अन्नपूर्णा योजना के तहत नाश्त प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक एवं दोपहर का भोजन प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक तथा रात्री का भोजन सांयकाल 7:00 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक उपलब्ध हो सकेगा। योजना के तहत बनाये जाने वाले नाश्तें एवं भोजन में स्वच्छता एवं पौष्टिकता का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा।

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा रसोई योजना के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने भोजन किया एवं उपस्थित दो महिलाओं मुन्नी देवी एवं कैलाशी को भोजन भी कराया।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ऊर्जा संरक्षण दिवस–2016 (14 दिसम्बर, 2016) के अवसर पर प्रदेश को प्राप्त ''राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरूस्कार–2016 (नेशनल एनर्जी कंजरवेशन अवार्ड–2016)'' के प्रतीक चिन्ह को भेंट किया एवं पुरूस्कार के संबंध में जानकारी दी।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने अन्नपूर्णा रसोई योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इससे पूर्व सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। अन्त में नगर निगम प्रांगण से 5 अन्नपूर्णा रसोई वैन को निर्धारित स्थलों के लिए रवाना किया गया।

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किये जाने वाले समस्त कार्यो का अन्य विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो के साथ होगा समावेश

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किये जाने वाले समस्त कार्यो को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो के साथ समावेश करें तथा इसके लिए विभागों से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाये।

यह निर्देश मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने नगर निगम मुख्यालय पर अन्नपूर्णा रसोई योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान जयपुर स्मार्ट सिटी कार्यालय में स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा के दौरान दिये।

जयपुर स्मार्ट सिटी कार्यालय में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होनें अधिकारियों को निर्देश दिये की शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरूस्त किया जाये तथा इस कार्य में सभी कर्मचारी/अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि जुटे। उन्होनें कहा कि नगर निगम की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति के लिए समय सीमा निर्धारित की जाये। इस दौरान उन्होनें घर–घर कचरा संग्रहण, कचरे से ऊर्जा एल.ई.डी. लाईट परियोजना, मैकेनिकल क्लीनिंग ऑफ रोड़ तथा राजस्व से जुड़ी नगरीय विकास कर वसूली जैसी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये।

बैठक में जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में तीन प्रस्तुतीकरण दिये गये जिसमें बताया गया कि जयपुर शहर के 16 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम बनाये जायेंगे। इसी प्रकार परकोटा स्थित 8 मुख्य सड़कों को स्मार्ट रोड़ के रूप में विकसित किया जायेगा तथा स्मार्ट सॉल्यूशन का समावेश करते हुए उक्त सड़कों पर साईकिल, पैदल एवं वाहनों के लिए अलग–अलग ट्रैक बनाये जायेंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विरासत संरक्षण एवं पुनःरूद्धार योजना में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, किशनपोल बाजार, पुराना टाउन हॉल, जलेब चोक, पुलिस मुख्यालय का संरक्षण एंव पुनरूद्धार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चार दिवारी के भीतर, रात्रि बाजार लगाये जायेंगे। इस संबंध में भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने परियोजना में किये जाने वाले कार्या की विस्तार से जानकारी ली एवं अब तक किये गये कार्यो कि समीक्षा की। उन्होनें अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किये जाने वाले समस्त कार्यो को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो के साथ समावेश करें तथा इसके लिए विभागों से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाये।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत द्वितीय राज्य स्तरीय कार्यशाला क्लीन एण्ड स्मार्ट राजस्थान का आयोजन 22 व 23 दिसम्बर, 2016 को उदयपुर में

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 22–23 दिसम्बर को उदयपुर में नगरीय निकायों के लिए द्वितीय कार्यशाला ''क्लीन एण्ड स्मार्ट राजस्थान'' का आयोजन होटल इन्दर रेजीडेन्सी, उदयपुर मे किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा किया गया।

इस अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले नगरीय निकायों जिला प्रशासन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को पुरूस्कृत किया गया।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि द्वितीय राज्य स्तरीय कार्यशाला ''क्लीन एण्ड स्मार्ट राजस्थान'' के अवसर पर डूंगरपुर को खुले में शौच मुक्त करने पर वहॉ के जिला कलेक्टर श्री सुरेन्द्र कुमार सौलंकी, सभापति श्री के.के.गुप्ता तथा आयुक्त श्री दिलीप गुप्ता को पुरूस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार देवली को खुले में शौच मुक्त करने के क्रम में वहॉ के उपखण्ड अधिकारी श्री मनोज कुमार शर्मा, अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती रेखा जैन व अधिशाषी अधिकारी श्री जर्नादन शर्मा को पुरूस्कृत किया गया।

कार्यशाला में सफाई व्यवस्था, पॉलीथीन प्रतिबन्ध एवं हैरिटेज संरक्षण के लिए जिला कलेक्टर नागौर एवं लाडनूं के उपखण्ड अधिकारी श्री मुरारी लाल अध्यक्ष नगरपालिका लाडनूं श्रीमती संगीता पारीक एवं अधिशाषी अधिकारी श्री भगवान सिंह को तथा स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने पर जिला कलेक्टर करौली श्री मनोज कुमार शर्मा, नगरपालिका करौली के सभापति श्री राजाराम गुर्जर एवं कार्यवाहक आयुक्त श्री खेमराज मीणा को तथा प्रतापगढ़ में कचरे जैविक खाद्य बनाने एवं घर–घर कचरा संग्रहण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए जिला कलेक्टर प्रतापगढ़, श्रीमती नेही गिरी, नगरपालिका प्रतापगढ़ के सभापति श्री कमलेश दोषी, आयुक्त श्री दीपक नागर को पुरूस्कृत किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य योजनाओं के उत्कृष्ठ सम्पादन के लिए स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा, मुख्य अभियन्ता श्री के.के.शर्मा, परियोजना निदेशक श्री एस.आर.मीणा, वरिष्ठ नगर नियोजक श्री आर.के.विजयवर्गीय, सचिव भर्ती आयोग श्रीमती अल्का मीणा, सहायक अभियन्ता श्री ओ.पी.काला एवं सीएमएआर की समन्यक डॉ हिमानी तिवाड़ी को पुरूस्कृत किया गया।

कार्यशाला में स्वच्छता एवं कच्ची बस्ती सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने पर जागृती स्वयं सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री जे.के.जाजू, वेस्ट मैनेजमेंट कम्पोस्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए आईएलएफएस, नई दिल्ली के श्री अरूण कुमार शर्मा, सामुदायिक सहभागिता एवं शौचालय निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने पर सेन्टर फॉर एडवोकेसी एण्ड रिसर्च की सुश्री पुनम कुलश्रेष्ठ तथा स्वच्छ भारत मिशन में जनसहभागिता के लिए कट्स इन्टरनेशनल जयपुर के जॉर्ज चेरियन एवं श्री अमरदीप सिंह को पुरूस्कृत किया गया।

प्रदेश के प्रत्येक शहर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने के साथ–साथ खुले में शौच मुक्त बनाया जायेगा

प्रदेश के प्रत्येक शहर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने के साथ–साथ खुले में शौच मुक्त बनाया जायेगा। सभी नगरीय निकायों को अपने–अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाये रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

इस अवसर पर नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग के मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने कहा कि प्रदेश को स्वच्छ सुन्दर एवं खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों को मुस्तेदी से कार्य करना होगा। उन्होनें कहा कि वर्ष 2017 में सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए प्रयास किये जायेंगे तथा सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता बनाये रखने के लिए वहॉ नियुक्त अधिकारियों को सख्त कदम उठाने होंगे, कैरिंग चार्ज वसूलना होगा तथा निकाय क्षेत्रों में स्थित बाजारों में हर दुकान के बाहर कचरा पात्र रखवाना होगा। घर–घर शौचालयों का निर्माण करवाना होगा तथा अपने–अपने नगरीय निकाय क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त बनाना होगा। इसके लिए सभी नगरीय निकायों में नियुक्त अधिकारियों को आवश्यक अधिकार दिये जायेंगे तथा इसके लिए आवश्यक हुआ तो नये नियम बनाये जायेंगे एवं पुराने नियमों में संशोधन कर जुर्माने की दरें बढ़ायी जायेंगी। उन्होने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं को खुला छोड़ने पर प्रभावी जुर्माना वसूल किया जायेगा। इसी प्रकार अवैध मीट की दुकानों से जुर्माना वसूल किया जायेगा तथा मीट के दुकानों की लाईसेंस की दरों में एवं होटल लाईसेंस की दरों में वृद्धि की जायेगी। उन्होनें कहा कि नगरीय निकायों में स्थित कांजी हाऊस की स्थिति को भी सुधारा जायेगा। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निकाय क्षेत्रों में खाली पड़े प्लॉटों को कचरागाह बनने से रोके तथा संबंधित भू–मालिकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें तथा वहॉ पड़े कचरे को हटवायें। उन्होनें निर्देश दिये कि प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में फायर स्टेशन बनाये जाये तथा वहॉ आवश्यक उपकरण एवं वाहन उपलब्ध करवाये जाये। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि कार्य योजना पर कार्य प्रारम्भ कर

दिया गया है तथा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सभी नगरीय निकयों में फायर स्टेशन बनवायें जायेंगे।

उन्होनें नगरीय विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जन आवास योजना, रिसर्जेन्ट राजस्थान समीट, प्रमुख बजट घोषणाओं विभिन्न पॉलिसियों, अधिनियमों एवं उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी ली। आवासन मण्डल की समीक्षा के दौरान उन्होनें अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मुकेश शर्मा को निर्देशित किया कि जिन कॉलोनियों को आवासन विभाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर चुका है। वहॉ स्थित प्लॉट/सम्पत्ति भी संबंधित नगरीय निकाय को हस्तांतरित की जाये। जिससे नगरीय निकाय की स्थिति सुदृढ़ हो सके। उन्होनें आवासन मण्डल के मकानों के प्रतीक्षाधारियों को शीघ्र मकान आवंटित करने के भी निर्देश दिये। नगर नियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान, विभिन्न योजनओं, भू–उपयोग परिवर्ततन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री वैभव गैलेरिया ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में जारी विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी साथ ही पृथ्वीराज नगर योजना, रिंग रोड़ परियोजना, द्रव्यवती नदी पुरोद्धार योजना, रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान किये गये एमओयू की प्रगति रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान के जयपुर मेट्रो परियोजना की भी समीक्षा की गई।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह ने स्वायत्त शासन विभाग एवं रूडसिको के कार्यो की समीक्षा के दौरान विभागीय गतिविधियों एवं योजनों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होनें बताया कि स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्टराज, स्मार्ट सिटी, आरओबी, आरयूबी निर्माण, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना), एनर्जी सेविंग परियोजना, ह्रदय, दीनदयास अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, सीवरेज परियोजना, उद्यान विकास कार्य, ठोस कचरा प्रबंधन, घर–घर कचरा संग्रहण, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आवास योजना आदि की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में घर–घर शौचालय बनाने के लिए 3.50 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके है। लगभग 2500 वार्ड प्रदेश में खुले में शौच मुक्त हो चुके है। इसी प्रकार देवली एवं डूंगरपुर खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके है। मार्च 2017 तक प्रदेश के 33 शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित बनाया जायेगा। ठोस कचरा

प्रबंधन के तहत प्रदेश के बड़े शहरों में कचरे से खाद्य एवं ऊर्जा बनाने तथा कचरा के प्रोसेसिंग के प्लांट लगाये जा रहे है। प्रदेश में नई सीवरेज निति लागू कर दी गई है। शीघ्र ही जयपुर शहर में एक पृथक वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड बनाया जायेगा। विभिन्न शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाये गये है तथा सीवरेज लाईनों को इनसे जोड़ा गया है। एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत प्रदेश में 12 लाख एलईडी लाईटें लगायी जायेगी। जिनमें से 5.50 लाख एलईडी लाईटें अब तक लग चुकी है। अमृत योजना के तहत प्रदेश के 29 शहरों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा राजस्थान इस योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। ह्रदय योजना के तहत अजमेर व पुष्कर में हैरिटेज संरक्षण के कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में अब 61 आरओबी/आरयूबी 1750 करोड़ रूपये की लागत से बनाये जाने है। जिनमें से 26 बन चुके है तथा 13 निर्माणाधीन है एवं शेष प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 29 परियोजनाएं स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। स्मार्ट सिटी के तहत प्रदेश के चारों शहरों में कार्य प्रगति पर है। बैठक में अन्नपूर्णा योजना की भी विस्तार से जानकारी दी गई।

उन्होनें बताया कि दीनदयास अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनके तहत स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से बेरोजगारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायें जा रहे है। प्रदेश में बेघर लोंगों के लिए 230 आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा चुका है तथा वेंडर जोन एवं नॉन वेंडर जोन सभी नगरीय निकायों में बनाये जा रहे है।

राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक सम्पन्न

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करते हुए पूर्ववत शर्तो पर भर्ती की प्रक्रिया की जावे

जिन नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। उनमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करते हुए पूर्ववत शर्तो पर भर्ती की प्रक्रिया की जावे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के दौरान उनसे तीन दिवसीय प्रायोगिक कार्य भी फिल्ड में करवाया जायेगा।

बैठक में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निर्णय लिया गया कि जिन नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। उनमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करते हुए पूर्ववत शर्तो पर भर्ती की प्रक्रिया की जावे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के दौरान उनसे तीन दिवसीय प्रायोगिक कार्य भी फील्ड में करवाया जायेगा। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि राजस्थान नगर पालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 एवं समय–समय पर विभाग द्वारा इस आशय में जारी दिशा–निर्देशों, आदेशों, परिपत्रों आदि के अनुसार प्रदेश के स्वच्छकारों व परंपरागत सफाईकर्मी परिवारों की विधवा/परित्यक्ता महिलाओं एवं विकलांगो का सर्वे कर उन्हें सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए जाने में आरक्षण नियमों की पालना की जावे।

बैठक में वर्ष 1990 से लम्बित, भंग नगरपालिका समदड़ी के मृतक सफाई कर्मचारी स्व0 श्री चूनाराम के आश्रित की अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरण के निस्तारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग मूल पत्रावली मंगाकर प्रकरण का निस्तारण करें। बैठक में ग्राम पंचायतों/पंचायतों, ख्यातनाम देवालयों/मंदिरों, वृहद राजकीय प्रतिष्ठानों/ कार्यालयों/संस्थानों/ विद्यालयो में नियमित सफाई कार्य करने वाले कर्मियों का नियमन किये जाने/यथोचित मानदेय/पारिश्रमिक/लाभ–परिलाभ नरेगा योजना के माध्यम से दिलवाये जाने की अनुशंषा की गई।

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, में विचाराधीन स्वच्छकार व परंपरागत सफाईकर्मी परिवारों के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न राजकीय विभागों में, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति/नियोजन हेतु संशोधित अधिसूचना जारी किए जाने के संबंध मे शीघ्र कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रदेश के स्वच्छकारों एवं प्रथागत सफाईकर्मियों

के पुर्नवास एवं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सम्बल हेतु राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अध्यधीन संचालित केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा एवं प्रगति की जानकारी एक सप्ताह में भिजवाने के निर्देश दिये गये।

राज्य सरकार के अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से प्रभावशील एवं संचालित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा व प्रगति की जानकारी के दौरान बताया गया कि 781 लोगों का ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में अब तक स्वच्छकारों द्वारा लिये गये सम्पूर्ण बकाया ब्याज माफ करने की आयोग द्वारा अभिशंषा किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक यह निर्णय भी लिया गया कि जिन सफाई कर्मचारियों को राजकीय सेवा में कार्य करते हुए दो वर्ष हो चुके है एवं उन्हें संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्थायी नहीं किया गया है। ऐसे कर्मचारियों को अविलम्ब स्थाई किये जाने के लिए निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग निर्देश जारी करेगा।

चियांगमे सिटी (थाईलैण्ड) को क्रियेटिव सिटी बनाये जाने के लिए 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने जयपुर शहर की विरासत कालीन कला एवं संस्कृति की ली जानकारीः स्वायत शासन भवन में कार्यशाला में दी जानकारी

चियांगमे सिटी (थाईलैण्ड) के महापौर श्री किटी बून के नेतृत्व 12 सदस्य प्रतिनिधि मण्डल ने गुरूवार को स्वायत्त शासन भवन में निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा से भेंट कर क्रियेटिव सिटी चयन की प्रक्रिया एवं जयपुर शहर की विरासत कालीन कलाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

कार्याशाला का आयोजन निदेशक एंव संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में किया गया। स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ नगर नियोजक श्री आर.के.विजयवर्गीय ने जयपुर शहर के विरासत कालीन वैभव, नगर नियोजन एवं कलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर विरासत फाउण्डेशन के विक्रम गोलेछा, विनोद शाह, इण्डियन इंस्टिट्यूट क्राफ्ट एवं डिजाइनर की निदेशक रश्मि पारीक, मास्टर क्राफ्टमैन श्री बादशाह मियां, श्री इन्दर सिंह, अरबाज खान ने विरासत कालीन मीनाकारी, लाख टेक्सटाईल्स एवं हस्तकलाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया।

उल्लेखनीय है कि यूनेस्को द्वारा जयपुर को गतवर्ष क्राफ्ट एवं लोक कला संस्कृति के लिये क्रियेटिव सिटी घोषित किया गया है। इसी प्रकार इस वर्ष भी यूनेस्को द्वारा क्रियेटिव सिटी का चयन किया जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। चियांगमे सिटी (थाईलैण्ड) भी यूनेस्को क्रियेटिव सिटी के लिये अपना प्रस्ताव प्रेषित करने जा रही है। इस संबंध में चियांगमे सिटी (थाईलैण्ड) का एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने वहॉ के महापौर श्री किटी बून के नेतृत्व में स्वायत्त शासन भवन में निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा से भेंट कर क्रियेटिव सिटी चयन की प्रक्रिया एवं जयपुर शहर की विरासत कालीन कलाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर एक कार्याशाला का भी आयोजन किया गया। जिसमें जयपुर की लोक कला एवं संस्कृति विरासत को समझने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर के हैरिटेज संरक्षण के लिए किये जा रहे कार्यो की जानकारी विस्तार से दी गई। कार्याशाला में क्रियेटिव सिटी के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण द्रोणा की

सलाहकार डॉ शिखा जैन द्वारा दिया गया। प्रस्तुतीकरण में जयपुर की विभिन्न हस्तकलाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।

चियांगमे सिटी (थाईलैण्ड) के महापौर किटी बून ने बताया कि उनका शहर बैंकाक के बाद थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है एव जयपुर शहर के समान ही वहॉ की जनसंख्या एवं विकास का क्रम है। वहॉ का क्राफ्ट एवं लोक कला भी जयपुर के समान है। उन्होनें कहा कि वे जयपुर की विरासत कालीन हस्तकलाओं से बेहद प्रभावित है। इन कलाओं को सम्मान देने के लिए यूनेस्को द्वारा गत वर्ष जयपुर को क्रियेटिव सिटी का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को के पूर्व सलाहकार एवं वर्तमान चियांगमे सिटी (थाईलैण्ड) के सलाहकार श्री रिचार्ड ने जयपुर शहर के नियोजन एवं विरासत कालीन भवनों के संरक्षण के लिए किये जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होनें कहा कि उनका शहर भी जयपुर के समान ही समृद्ध है तथा क्रियेटिव सिटी के दर्जे के लिए यूनेस्कों में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा है।

शहरी विकास मंत्रालय की क्यूसीआई टीम करेगी प्रदेश के 29 शहरों की स्वच्छता के लिए करेगी आंकलन एंव मूल्यांकन

स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के तहत शहरी विकास मंत्रालय की क्यूसीआई टीम प्रदेश के 29 शहरों अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, कोटा, नागौर, सीकर, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, झालावाड़, टोंक, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, गंगापुर सिटी, हिण्डौन, झुझुनूं, किशनगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, सवाईमाधोपुर, सुजानगढ़ व उदयपुर में की सफाई व्यवस्था का आंकलन एवं मूल्यांकन (रेंकिंग) करेगी। प्रदेश में 04 जनवरी, 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 प्रारम्भ हो गया है।

निदेशक एंव संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश में 04 जनवरी, 2017 से प्रारम्भ हुये स्वच्छता सर्वेक्षण–2017 के तहत शहरी विकास मंत्रालय की क्यूसीआई टीम शहरों के आंकलन एवं मूल्यांकन (रेंकिंग) 27 जनवरी, 2017 से 29 जनवरी, 2017 तक अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, कोटा, नागौर, सीकर में तथा 30 जनवरी, 2017 से 01 फरवरी, 2017 तक बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, झालावाड़, टोंक में एवं 02 फरवरी, 2017 से 04 फरवरी, 2017 तक बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, गंगापुर सिटी, हिण्डौन, झुझुनूं, किशनगढ़ में व 05 फवरी, 2017 से 07 फरवरी, 2017 तक गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, सवाईमाधोपुर, सुजानगढ़ व उदयपुर में करेगी।

उन्होने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 का आंकलन, मूल्यांकन शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित क्यूसीआई की टीम द्वारा किया जायेगा। प्रदेश के 29 शहरों में शहरी विकास मंत्रालय की क्यूसीआई टीम सम्बन्धित नगरीय निकायों का भ्रमण कर वहां के नागरिकों सफाई व्यवस्था व अन्य घटकों का आंकलन कर स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मूल्यांकन (रेंकिंग) करेगी। इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदेश के 29 शहरों जो स्वच्छता सर्वेक्षण में सम्मिलित हैं, को रेंकिंग हेतु पूर्व में प्रशनावली भेजी जा चुकी है तथा इस संबंध में एक कार्यशाला का 26 अक्टूबर, 2016 को आयोजन कर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पूर्ण जानकारी विस्तार से दी जा चुकी है। इस कार्यशाला में सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया जा चुका है कि वे स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए एक नोडल अधिकारी निर्धारित करते हुए अपनी–अपनी नगरीय निकाय का स्वनिर्धारण करते हुए सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे तथा जब भी शहरी विकास मंत्रालय की क्यूसीआई टीम नगरीय निकाय में चाहेगी उससे सम्पर्क कर कार्य सम्पादित करेंगे।